Golden Research Thoughts
Volume 2, Issue. 7, Jan. 2013
ISSN:-2231-5063
Available online at www.aygrt.net

ORIGINAL ARTICLE

पोखरण–II : भारतीय परमाणविक नीति में युगान्तकारी परिवर्तन

जयश्री

शोध छात्रा (राजनीति विज्ञान) जी.एस.एच. कॉलेज, चान्दपुर–स्याऊ (बिजनौर) उत्तर प्रदेश (भारत)

सारांश

अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही भारत 'परमाणु अस्त्र विहीन विश्व' की नीति का समर्थक रहा है। यद्यपि परमाणु तकनीक का, शांतिपूर्ण एवं विकासात्मक उद्देश्यों हेतु प्रयोग किये जाने का भारत सदैव पक्षधर रहा है तथापि अपनी भू–राजनीतिक आवश्यकताओं एवं वृहत्तर राष्ट्रीय हितों को दृष्टिगत रखते हुए, अपने परमाणु विकल्पों को खुला रखना एवं 'न्यूनतम किन्तु विश्वसनीय परमाणु निरोधक क्षमता' को बनाये रखने का निर्णय भारतीय परमाणविक नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ का सूचक है। पोखरण II के पश्चात भारत की 'शान्तिपूर्ण परमाणु नीति' न सिर्फ 'स्वतन्त्र परमाणु नीति' में परिवर्तित हो गयी, वरन् इसने भारत की 'महान परमाणु सामर्थ्य' को भी स्पष्ट कर दिया। प्रस्तुत शोध पत्र में पोखरण II एवं तत्कालीन उपमहाद्वीपीय परिस्थितियों का विश्लेषण भारतीय राजनय के सन्दर्भ में किया गया है।

प्रमुख बिन्दु:–

एन.डी.ए. सरकार की परमाणविक नीति, गोरी मिसाइल का परीक्षण, परमाणु विस्फोट, विश्लेषण एवं महत्व।

प्रस्तावना :–

सम्प्रति विश्व अनेक प्रकार के संकटों, परिवर्तनों, चुनौतियों एवं संक्रमण से गुजर रहा है। आधुनिक विश्व के समक्ष एक प्रमुख चुनौती निरन्तर बढ़ रहे परमाणु आयुधों एवं परमाणु शस्त्र धारक देशों की बढ़ती संख्या के रूप में प्रत्यक्ष है। यद्यपि 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही भारत परमाणु निरस्त्रीकरण का एक प्रमुख पक्षधर एवं परमाणु शस्त्रीकरण का घोर विरोधी रहा है तथापि इसने परमाणु तकनीक के शान्तिपूर्ण उपयोग एवं उच्च तकनीक का, विकासपरक उद्देश्यों के लिये विकासशील देशों को हस्तान्तरण का सदैव समर्थन किया। मई 1974 में अपने प्रथम परमाणु विस्फोट के बाद भी भारत ने शान्तिपूर्ण परमाणु उपयोग की नीति ने प्रति पूर्ण वचनबद्धता बनाये रखी। इस सबके बावजूद अपनी भू–राजनीतिक एवं भू–क्षेत्रीय परिस्थितियों, वृहत्तर राष्ट्रीय हितों के अनुरक्षण एवं एन.पी.टी. तथा सी.टी.बी.टी. जैसी विभेदकारी नीतियों को स्वीकारने हेतु पड़ते अन्तर्राष्ट्रीय दबावों की पृष्ठभूमि में भारत ने परमाणु शस्त्र धारक देश बनने का निर्णय किया जो भारतीय परमाणविक नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ का द्योतक बना।

इस हेतु वस्तुतः, मार्च 1998 में भारत में हुए युगान्तकारी सत्ता परिवर्तन के साथ ही नवगठित सरकार ने अपनी समरनीति में आवश्यक परिवर्तन[1] करने शुरू कर दिये। चूंकि भाजपा अपने चुनावी घोषणा–पत्र में परमाणु विकल्प को खुला रखने की वकालत कर चुकी थी अतः अब उसने इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिये। इसके प्रारंभिक संकेत नवनियुक्त रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नांडीस के उस बयान से मिलने प्रारम्भ हो गये जिसमें उन्होंने कहा था कि "भारत की सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता और एकता सुनिश्चित करने के लिये हम सभी आवश्यक कदम उठाएंगे और इस सन्दर्भ में हम अपनी परमाणु नीति का फिर से आकलन करेंगे तथा परमाणु हथियारों का समावेश करने के लिये अपने विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे।" श्री फर्नांडीस ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि "हमारी सुरक्षा नीति किसी खास क्षेत्र पर केन्द्रित कर, आधारित नहीं की जा सकती वरन् इसे व्यापक भू–राजनैतिक वास्तविकता के मद्देनजर ही आधारित किया जाना चाहिये। ....भारत की नीति रक्षात्मक होगी न कि आक्रामक।"[2] इस प्रकार श्री फर्नांडीस ने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि भारत की परमाणविक नीति किसी राष्ट्र विशेष को लक्ष्य करके नहीं वरन वैश्विक संदर्भों में अपनी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बनायी गयी है।

भारत में सत्ता परिवर्तन के कुछ समय बाद ही 6 अप्रैल 1998 को पाकिस्तान ने 1500 कि.मी. दूरी तक मार करने वाली व परमाणु अस्त्रों को ले जाने में सक्षम मध्यम दूरी की मिसाइल हत्फ–5 (गोरी) का परीक्षण किया।[3] इस मिसाइल का नामकरण 12वीं सदी में भारत पर आक्रमण करने वाले अफगान शासक शिहाबद्दीन मुहम्मद गोरी के नाम पर किया गया।[4] इस मिसाइल के बारे में पाक वैज्ञानिकों की ओर से दावा किया गया कि यह भारत के अधिकांश शहरों को निशाना बनाने में सक्षम है।[5] पाकिस्तान ने इस मिसाइल को सियालकोट से करांची तक करीब छः स्थानों पर भारत से लगने वाली पाक सीमा पर तैनात करने की योजना बनाई। इस मिसाइल की जद में दिल्ली के अलावा, मुम्बई, चेन्नई, अहमदाबाद, ट्राम्बे, नागपुर, जालन्धर, जैसलमेर व पटना जैसे कई प्रमुख शहर व परमाणु प्रतिष्ठान आने वाले थे।[6] पाकिस्तान के द्वारा गोरी के परीक्षण ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक नया भू–सामरिक परिदृश्य उत्पन्न कर दिया।[7] इस सम्बन्ध में भारतीय चिन्ता का मुख्य कारण यह था कि गोरी मिसाइल द्वारा पाकिस्तान भारत के दक्षिण व पूर्व के कई प्रमुख शहरों तक वार कर सकता था। चूंकि पाकिस्तान के पास अब परमाणु बम भी उपलब्ध थे अतः भारतीय रक्षा –प्रतिष्ठान को चिन्ता थी कि गोरी के द्वारा पाकिस्तान अब भारत पर परमाणु हमला भी कर सकता

है तथा स्वयं को उसके रेडियोधर्मी विकिरण के दुष्प्रभाव से बचा भी सकता है।

यद्यपि भारतीय रक्षा मंत्री श्री फर्नांडीस बार–बार यह कहते रहे कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में 'पृथ्वी' प्रक्षेपास्त्र हैं अतः उसे पाकिस्तान से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।8 तथापि गोरी मिसाइल के परीक्षण ने भारत की ''रक्षा चिन्ताओं में वृद्धि'' अवश्य की। इसी बीच पाकिस्तान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक डॉ. अब्दुल कादिर खान ने दावा किया कि पाकिस्तान शीघ्र ही परमाणु विस्फोट के लिये तैयार है। उन्होंने कहा ''हम किसी भी समय परमाणु विस्फोट करने के लिये तैयार हैं और जिस दिन राजनीतिक निर्णय हो जाएगा हम इसे दुनिया को दिखा देंगे।'' इसके अतिरिक्त उन्होंने यह दावा भी किया कि पाकिस्तान सतह से सतह पर मार करने वाला एक अन्य प्रक्षेपास्त्र भी बना रहा है जिसकी मारक क्षमता गोरी से बहुत अधिक–लगभग 2000 कि.मी.–होगी।9इस संदर्भ में पाकिस्तानी विदेशमंत्री गौहर अयूब खान ने तो भारत को यह कहते हुए चेतावनी तक दे डाली कि ''गोरी प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण तो अभी शुरूआत है तथा न तो भारत और न ही किसी विकसित देश के पास गोरी प्रक्षेपास्त्र को गिराने की क्षमता है।''[10] पाकिस्तान के इन तमाम उत्तेजक बयानों पर भारत ने काफी संयम से काम लिया। वास्तव में इस संदर्भ में भारत का दृष्टिकोण यह था कि संयम के द्वारा उपमहाद्वीप में तनाव को बढ़ने से रोका जाए जबकि पाकिस्तान में इसका अर्थ यह लगाया गया कि भारत पाकिस्तान की ताकत के आगे झुक गया है। इस प्रकार गोरी मिसाइल के परीक्षण और उसके बाद उपजी परिस्थितियों ने उपमहाद्वीपीय वातावरण को विषाक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस परिदृश्य में 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण रेगिस्तान में दोपहर तीन बजकर 45 मिनट पर एक साथ तीन भूमिगत परमाणु परीक्षण किये। इनमें एक परीक्षण कम क्षमता वाला, एक विखण्डनीय (फिशन) परीक्षण और तीसरा थर्मोन्यूक्लियर परीक्षण था। इन परीक्षणों की घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई को सायं 6 बजे अचानक आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में की। उन्होंने बताया कि इन परीक्षणों में किसी भी तरह की रेडियोधर्मिता नहीं पायी गयी।[11] भारत द्वारा इस प्रकार परमाणु परीक्षण किये जाने पर सम्पूर्ण विश्व में नकारात्मक प्रतिक्रिया हुई। लेकिन तमाम अन्तर्राष्ट्रीय धमकियों व दबावों को धता बताते हुए भारत ने 13 मई 1998 को दोपहर 12 बजकर 21 मिनट पर एक किलो टन क्षमता से कम के दो अन्य भूमिगत परमाणु परीक्षण किये।[13] इन परीक्षणों के बाद भारत ने घोषणा की कि पोखरण–II श्रृंखला (इसे शक्ति–श्रृंखला–98 के नाम से भी जाना गया) के परमाणु परीक्षण का नियोजित कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका है तथा भारत अब एक परमाणु शस्त्र धारक देश है।[14] भारत द्वारा किये गए इन परमाणु परीक्षणों (पोखरण– II श्रृंखला) को निम्न सारणी 15 से स्पष्ट समझा जा सकता है–

परीक्षण संख्या	परीक्षण के प्रकार	समय	दिनांक	अनुमानित उर्जा उत्सर्जन
01	थर्मोन्यूक्लियर (तापीय परमाणविक)	15.45	11.5.98	45 किलो टन
02	फिशन (विखण्डनीय)	15.45	11.5.98	15 किलो टन
03	कम तापीय	15.45	11.5.98	0.2 किलो टन
04	कम तापीय	12.21	13.5.98	0.5 किलो टन
05	कम तापीय	12.21	13.5.98	0.5 किलो टन

11–13 मई 19998 को किये गए ये परमाणु परीक्षण भारत की परमाणविक नीति में युगान्तकारी मोड़ के द्योतक थे। इनके द्वारा भारत विश्व में 'छठी परमाणु शक्ति' के रूप में उभरा।[16] उल्लेखनीय है कि 18 मई 1974 को भारत द्वारा पोखरण में ही किये गए 'शान्तिपूर्ण परमाणु विस्फोट'[17] (पोखरण– I) के बाद से ही प्रायः सभी भारत सरकारों ने अपने परमाणविक विकल्प को खुला रखा था परन्तु किसी भी सरकार ने परमाणु परीक्षण का जोखिम नहीं उठाया। वैसे 1995 में नरसिंहराव सरकार परमाणु परीक्षण के लिये तैयार हो गयी थी परन्तु समय रहते इसका अमरीका को पता चल गया और उसने दबाव डालकर राव सरकार को ऐसा करने से रोक दिया।[18] इसके विपरीत 1998 के परमाणु परीक्षणों में पूरी गोपनीयता बरती गई।[19] यद्यपि भाजपा गठबंधन सरकार ने सत्ता–ग्रहण के अगले ही दिन परमाणु परीक्षण करने का निर्णय ले लिया था तथापि प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने अपनी केबिनेट को भी इस निर्णय की भनक न लगने दी और केवल गृहमंत्री, रक्षामंत्री और वित्त मंत्री को इसकी ही जानकारी दी। पोखरण–I और पोखरण–II में एक अद्भुत समानता यह थी कि ये दोनों ही परीक्षण 'बुद्ध पूर्णिमा' के दिन सम्पन्न हुए।[20] वास्तव में कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नेताओं द्वारा लिये गए प्रारम्भिक नीतिगत निर्णयों के बाद यह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय था।[21] इसके फलस्वरूप भारत ने यह घोषणा कर दी कि वह परमाणु शस्त्र सम्पन्न राष्ट्र है। इस प्रकार वर्षों से चली आ रही असमंजस की स्थिति समाप्त हो गयी कि क्या भारत को परमाणु बम बनाना चाहिये अथवा नहीं।' वस्तुतः 'पोखरण में परमाणु धमाकों के साथ ही हिन्दुस्तान ने यह ऐलान कर दिया कि वह परमाणु आयुध सम्पन्न राष्ट्र है और इस तरह बरसों से चली आ रही असमंजस की स्थिति समाप्त हो गयी। विदेश नीति और रणनीति के संदर्भ में जो अब तक एक 'विकल्प' था वह अब 'वास्तविकता' में बदल चुका था। निश्चय ही यह एक ऐसा फैसला था जिसे 'ऐतिहासिक' और 'निर्णायक' माना जा सकता है।[22]

17 मई 1998 को नयी दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को 'शक्ति–98' (पोखरण.II) अभियान से जुड़े शीर्ष वैज्ञानिकों ने पहली बार सम्बोधित किया। इसमें रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. आर. चिदम्बरम, भाभा परमाणु शोध केन्द्र (बी.ए.आर.सी.) के निदेशक डॉ. अनिल काकोडकर तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.)के प्रमुख तकनीकी सलाहकार डॉ. के. सन्थानम उपस्थित थे। अपने सम्बोधन में इन शीर्ष वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने परमाणु शस्त्रीकरण का काम पूरा कर लिया है। भाभा परमाणु शोध केन्द्र के निदेशक डॉ. अनिल काकोडकर ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों से कई उपयोगी आंकड़े प्राप्त किये जा सके हैं एवं अब भारत जरूरत पड़ने पर कम्प्यूटर अनुकरण आधारित अपक्रान्तिक (सबक्रिटिकल) परीक्षण करने में पूर्ण सक्षम है।[23] इस संदर्भ में 15 मई 1998 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने निवास स्थान पर इण्डिया टुडे (पत्रिका) को दी गई एक भेंटवार्ता में स्पष्ट कर दिया कि, ''हमारे पास एक बड़ा बम है जिसकी कमान हेतु एक नियंत्रक प्रणाली मौजूद है। हम अपने आयुध का निर्माण आक्रमण के लिये नहीं करेंगे।'' उन्होंने कहा कि, ''हम अपने परमाणु विस्फोटों पर अनावश्यक रूप से सन्देह का आवरण नहीं डालना चाहते। भारत अब एक परमाणु आयुध सम्पन्न राष्ट्र बन चुका है।'' भारत के इरादे शान्तिपूर्ण ही हैं इस पर जोर देते हुए श्री वाजपेयी ने कहा, ''हमारे इरादे शान्तिपूर्ण थे और शान्तिपूर्ण रहेंगे।''[24] 27 मई 1998 को भारतीय संसद के समक्ष भारत की परमाणु नीति के विकास पर प्रस्तुत पत्र 25 तथा 29 मई को राज्यसभा में परमाणु परीक्षण के बारे में प्रश्नों के उत्तर देते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने इस मत की अभिपुष्टि की।[26] 27 मई 1998 को

DSpace™

लोकसभा में प्रधानमंत्री ने पुनः दोहराया कि, ''भारत अब एक परमाणु हथियारों से सम्पन्न देश है। यह एक सच्चाई है जिसे कोई नकार नहीं सकता। .....हमारी इच्छा किसी के विरूद्ध इन हथियारों का इस्तेमाल करने की नहीं है। हमारी यह शक्ति किसी देश को धमकाने के लिये नहीं है। ये हथियार आत्मरक्षा के लिये हैं..... हम किसी के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहते।''[27] 21 मई 1998 को नई दिल्ली में विदेश मन्त्रालय द्वारा आयोजित एक पत्रकार वार्ता में प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी के प्रधान सचिव श्री बृजेश मिश्र ने जानकारी दी कि ''भारत अब और परमाणु परीक्षण नहीं करेगा।''[28]

पोखरण–II के दो मूल उद्देश्य थे। प्रथम–परीक्षणों से अतिरिक्त उपयोगी आंकड़े जुटाना और द्वितीय–आवश्यकता होने पर कम्प्यूटर अनुकरण आधारित अपक्रान्तिक (सब–क्रिटिकल) परीक्षण – प्रयोगशाला परीक्षण – के लिये क्षमता प्राप्त करना। शक्ति शृंखला (पोखरण–II) के अन्तर्गत इन्हें प्राप्त कर लिया गया।[29] 13 मई को किये गए अपक्रांतिक परीक्षणों से स्पष्ट हुआ कि भारत अब प्रयोगशालाओं में कम्प्यूटर आधारित परीक्षणों की ओर बढ़ रहा है। 11 मई को किये गए 03 परमाणु परीक्षणों में भी एक परीक्षण लो–ईल्ड अर्थात कम क्षमता वाला था जिसका उद्देश्य सबक्रिटिकल टेस्ट करना था। वर्तमान समय में सबक्रिटिकल टेस्ट की क्षमता केवल अमरीका के पास है। ध्यातव्य है कि सबक्रिटिकल टेस्ट को सम्पन्न करने के लिये जिस शक्तिशाली कम्प्यूटर की आवश्यकता थी उसका विकास मार्च 1998 के अन्तिम दिनों में ही भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किया जा चुका था।

13 मई के परीक्षणों से यह भी स्पष्ट हुआ कि अब भारत को भूमिगत, हवा या समुद्र में परमाणु परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी तथा भारतीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला में ही परीक्षण के आधार पर परमाणु डिजाइन कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि सी.टी.बी.टी. के प्रावधानों के अंतर्गत सबक्रिटिकल टेस्ट या कम्प्यूटर आधृत प्रयोगशाला परीक्षण करने पर कोई रोक नहीं लगायी गयी थी।[30] इन परीक्षणों के बाद भारत वह पहला देश बन गया जिसने एक दिन में ही नहीं वरन् एक साथ अलग–अलग प्रकार के तीन परीक्षण किए अतः इस घटना ने बात की भी पुष्टि कर दी कि भारत ने 1974 के बाद परमाणु क्षेत्र में काफी प्रगति की है, यह अलग बात है कि परीक्षण न करने का उनका संयम बना रहा। इस प्रकार इन विस्फोटों ने भारत की 'महान परमाणु सामर्थ्य'[31] को प्रस्तुत किया।

निष्कर्षतः

कहा जा सकता है कि पोखरण–II तत्कालीन भारत सरकार का एक अति महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय रहा। इस निर्णय ने न सिर्फ उपमहाद्वीप में एक नये भू–सामरिक परिदृश्य को जन्म दिया वरन् वैश्विक रंगमंच पर एक 'नये एवं सशक्त भारत' की छवि को भी मजबूत किया।

सन्दर्भः–

1.रंजीत कुमार, 'समर–नीति में क्रांतिकारी बदलाव' नवभारत टाइम्स (नयी दिल्ली) 20 मार्च 1998.
2.The Times of India (New Delhi) March 21, 1998.
3.Kapil Kak, 'Pakistan's Ballistic Missiles' : "Sword-Arm of a New Enfluential?' Asian Strategic Review: 1997-98, page- No.283 (IDSA New Delhi, 1998).
4.Anwar Ahmad, ' Gauri Versus Prithvi' The news (Islamabad) April 20, 1998.
5.Ruchita Beri, 'Pakistan's Missile Programme' Jasjit Singh (Ed.)- Nuclear India, Page no 194-196 (Knowledge world, New Delhi, 1998).
6.The Times of India (New Delhi) April 08, 1998.
7.Ahmed Rashid,'Ghauri Creats New Geo-Political Scenario' The Nation (Islamabad) April 14, 1998.
8.Hindustan Times (New Delhi) April 10, 1998.
9.The Times of India (New Delhi) April 17, 1998.
10.Hindustan Times (New Delhi) April 18, 1998.
11.The Times of India (New Delhi) May 12, 1998.
12.'Chronology of Responses to Pokharan- II' Strategic Digest, July 1998, Vo. XXVII, NO.07, Page No. 1091 (IDSA New Delhi, 1998).
13.Hindustan Times (New Delhi) May 14, 1998.
14.The Times of India (New Delhi) May 16, 1998.
15.S.K. Sikka and Anil Kakodkar, 'Some preliminary Results of May 11-13, 1998 : Nuclear Detonations at Pokharan' Strategic Digest, July 1998, Vol. XXVIII, No. 07, Page No. 1086 (IDSA New Delhi, 1998).
16.Jasjit Singh, 'India: The Sixth State with Nuclear Weapons' (Ed.) -Asian Strategic Review: 1997-98, Page No. 09-29 (IDSA New Delhi, 1998).
17.K. Subrahmanyam, 'Indian Nuclear Policy: 1964-98 (A Personal Recollection)' Jasjit Singh (Ed.)- Nuclear India, Page NO. 29-33 (Knowledge World, New Delhi, 1998).
18.विपिन चन्द्र आदि–आजादी के बाद का भारत (1947–2000) पृ. सं. 390 (हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 2002).
19.भूपेन्द्र कुमार स्नेही, 'पोखरण के लिये खेल गोपनीयता का' हिन्दुस्तान (नयी दिल्ली) 16 मई 1998.
20.The Times of India (New Delhi) May 17, 1998.
21.जे.एन. दीक्षित–भारत की विदेश नीति, पृ. सं. 399 (प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 1999).
22.पुष्पेश पंत,'पोखरण विस्फोट और उसके बाद' नवभारत टाइम्स (नयी दिल्ली) 15 मई 1998.
23.The Times of India (New Delhi) May 18, 1998.
24.Ibid. May 16, 1998.
25.'Paper Laid on the Table of the House on Evolution of India's Nuclear Policy' Strategic Digest, July 1998, Vol. XXVII; No. 07, Page No. 1079 -1084 (IDSA New Delhi, 1998).

DSpace™

26.'P.M's Reply to the discussion in Rajya Sabha on Nuclear Tests 29-5-98' Strategic Digest, Oct 1998, Vol.XXVII, No-10, Page No. 1583-1585 (IDSA New Delhi, 1998)
27.अटल बिहारी वाजपेयी–मेरी संसदीय यात्रा : राष्ट्रीय स्थिति, डॉ. ना. भा. घटाटे (सम्पा.) पृ. सं. 292–293 (प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2000).
28.The Times of India (New Delhi) May 25, 1998.
29.Hindustan Times (New Delhi) May 14, 1998.
30.रंजीत कुमार, 'भारत की नजर अब कम्प्यूटरों के जरिये परमाणु परीक्षणों पर' नवभारत टाइम्स (नयी दिल्ली) 13 मई 1998.
31.सविता पाण्डेय, 'प्रतिबन्धों से अहम है, राष्ट्रीय सुरक्षा' वही, 16 मई 1998 .